प्रशिक्षण ही हमारी पार्टी को अन्य दलों से अलग बनाता है- भजनलाल

राष्ट्रीय सहसंयोजक सांसद बीडी शर्मा ने कहा कि प्रशिक्षण भाजपा का संगठनात्मक कौशल विकास कार्यक्रम है

जयपुर 28 अप्रैल । भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मंगलवार से 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026' का शुभारंभ हुआ। प्रशिक्षण महाभियान को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रशिक्षण हमारी ताकत है। हमारे कार्यकलाप और विचारधारा ही प्रशिक्षण का आधार है। हम पहले राष्ट्र,

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे कार्यकलाप, विचारधारा ही प्रशिक्षण का आधार हैं। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि जो सीखता है, वह बढ़ता है, जो सीखना बंद कर देता है, वह बढ़ना भी बंद कर देता है।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026' का शुभारंभ किया।इस अवसर पर महाभियान के राष्ट्रीय सह संयोजक एवं सांसद वीडी शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद थे।

फिर पार्टी और अंत में स्वयं के लिए कार्य करते है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रशिक्षण ही हमारी पार्टी को अन्य दलों से अलग बनाता है। एक समय था, जब विपक्ष पंचायत से पार्लियामेंट तक था, लेकिन आज कहां पहुंच गया, सबके सामने है।

इसका मुख्य कारण उस संगठन में प्रशिक्षण अभियान की कमी, संगठन की रीति और नीति का अभाव है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं, अपने कार्य को हथियार बना लो, पार्टी आप को मौका अवश्य देगी। कार्यकर्ताओं को कार्य देना और उसका परिणाम लेना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमें सभी कार्यकर्ताओं को समान व्यवहार के साथ कार्य का बंटवारा करना चाहिए।

इस अवसर पर महाभियान के राष्ट्रीय सह संयोजक एवं सांसद वीडी शर्मा ने जिला प्रभारियों और जिलाध्यक्षों को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026 भाजपा का एक प्रमुख वैचारिक और संगठनात्मक कौशल विकास कार्यक्रम है, जो बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कार्यकर्ताओं को एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सिद्धांतों में प्रशिक्षित करता है। इसका उद्देश्य पार्टी विचारधारा को मजबूत करना, कार्यपद्धति में निखार लाना और डिजिटल माध्यमों से कार्यकर्ताओं को आधुनिक बनाना है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड ने कहा कि प्रशिक्षण तराशने की प्रक्रिया है। जो सीखता है, वह बढ ता है, जो सीखना बंद कर देता है, वो बढ ना भी बंद कर देता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति निर्माण से ही संगठन का निर्माण होता है।

इस दौरान मंच पर प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगडी, भूपेन्द्र सैनी, कैलाश मेघवाल, प्रशिक्षण महाभियान में प्रशिक्षण के प्रदेश संयोजक मिथिलेश गौतम, सह संयोजक मनीष पारीक, जगदीश धानदिया, महिला मोर्चा प्रदेश प्रभारी संतोष अहलावत उपस्थित थे।

रूस मध्यस्थता को तैयार, ईरानी विदेश मंत्री तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे

तेहरान/मास्को, 28 अप्रैल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 27 अप्रैल को मुलाकात करने के बाद ईरान के विदेशमंत्री अब्बास अराघची एक बार फिर पाकिस्तान पहुंचे हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर चल रहे टकराव के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं।

- **ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची की 48 घंटे में यह तीसरी पाकिस्तान यात्रा है।**

पुतिन ने कहा कि रूस मध्य पूर्व में जल्द से जल्द शांति सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने को तैयार है।

ईरान के प्रेस टीवी और रूस की समाचार एजेंसी तास की रिपोर्ट के अनुसार, अराघची के पाकिस्तान पहुंचने के बाद अमेरिका-ईरान युद्ध खत्म होने को लेकर अटकलें तेज हो गई है।

अराघची मंगलवार को रूस दौरे के बाद एक बार फिर 48 घंटे में तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे हैं।

एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट ठप्प होने के कगार पर

मिडिल ईस्ट संकट के कारण ईंधन की बढ़ती कीमतों ने खतरे की घंटी बजाई

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 अप्रेल। मध्य-पूर्व संकट ने भारत के विमानन क्षेत्र में चेतावनी की घंटी बजा दी है, कई एयरलाइंस ने चिंता जताई है कि उच्च ईंधन कीमतों के कारण वे "संचालन बंद करने" की कगार पर हैं। कम से कम तीन एयरलाइंस, जिनमें टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया शामिल है, ने सरकार से एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमतों में संशोधन करने का अनुरोध किया है, जो एक एयरलाइन के संचालन लागत का लगभग 40 प्रतिशत बढ़ा देता है।

फैडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइन्स (एफआईए) ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा है, "... किसी भी अस्थायी मूल्य निर्धारण (घरेलू बनाम अंतरराष्ट्रीय) और/या एटीएफ की अतार्किक वृद्धि एयरलाइंस के लिए असहनीय नुकसान का कारण बनेगी और इसके

- **तीनों एयरलाइंस ने कहा कि ईंधन की कीमतें बढ़ने से उनकी लागत 40 प्रतिशत बढ़ गई हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार से तुरंत दखल देने और विमानों के ईंधन "एटीएफ" की बढ़ती कीमतों को देखते हुए आर्थिक पैकेज देने की मांग की।**

परिणामस्वरूप विमान जमीन पर खड़े हो जायेंगे, जिससे उड़ानें निरस्त करनी पड़ेंगी।"

एफआईए में एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट शामिल हैं।

26 अप्रैल को लिखे इस पत्र में एफआईए ने कहा है, "जीवित रहने, संचालन बनाए रखने और जारी रखने के लिए, तथा वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए हम आपकी त्वरित और सार्थक वित्तीय मदद के अत्यावश्यक हस्तक्षेप का अनुरोध करते हैं।"

फैडरेशन ने कहा कि लॉन्ग-हॉल रूट्स पर उड़ानें सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने मंत्रालय से अनुरोध किया कि राहत के लिये ईंधन मूल्य निर्धारण की विधि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संचालन दोनों में समान हो, जैसा पहले किया गया था, जिसे "क्रैक बैंड" कहा जाता है।

"क्रैक बैंड" एक ऐसी एटीएफ मूल्य निर्धारण प्रणाली है जो कच्चे तेल और परिष्कृत एटीएफ की कीमतों के बीच अत्यधिक अंतर को रोकती है।

सरकार ने घरेलू संचालन के लिए एटीएफ की कीमत में वृद्धि को 15 रुपये प्रति लीटर तक सीमित कर दिया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संचालन के लिए यह वृद्धि 73 रुपये प्रति लीटर कर दी गई।

बंगाल में दूसरे व अंतिम चरण का मतदान आज

कुल 142 सीटों पर मतदान होगा जिन पर 1448 प्रत्याशी मैदान में हैं

कोलकाता, 28 अप्रैल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के अंतर्गत राज्य की 142 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार को मतदान होगा। अंतिम चरण में राजधानी कोलकाता के अलावा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली, नदिया और पूर्व बर्धमान जिलों में मतदान कराए जाएंगे।

इस चरण में एक हजार 448 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने सभी 142 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 141 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, दूसरे चरण के लिये एक हजार 463 नामांकन प्राप्त हुए। इनमें 15 लोगों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। दक्षिण 24 परगना के भांगड़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 19 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि सबसे कम पांच उम्मीदवार हुगली की गोघाट (एससी) सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में सात जिलों के कुल

- **दूसरे चरण में भवानीपुर सीट पर भी मतदान होगा जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं।**

तीन करोड़ 21 लाख73 हजार 837 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें एक करोड़ 64 लाख 35 हजार627 पुरुष तथा एक करोड़ 57 लाख 37 हजार 418 महिला मतदाताओं के अलावा, 792 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं।

इस चरण में कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट पर सबकी नजरें टिकी है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला नेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार शुभेन्दु अधिकारी से है। वर्ष 2021 के चुनाव में नंदीग्राम में दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था, जिसमें शुभेन्दु अधिकारी ने जीत दर्ज की थी।

शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिये चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। लगभग सभी मतदान केन्द्रों पर केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और संवेदनशील व अति-संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। वेबकास्टिंग, सीसीटीवी निगरानी और लगातार फ्लैग मार्च के जरिए शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है।

चुनाव आयोग सूत्रों के अनुसार, सबसे अधिक उत्तरी 24 परगना जिले में कुल 507 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। उत्तर 24 परगना के बारासात पुलिस जिले में 112 कंपनियों की तैनाती की जा रही हैं, जबकि बनगांव जिले में 62 कंपनी बल की तैनाती की जा रही है। इसी तरह अन्य जिलों में भी शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।

गत 23 अप्रैल को पहले चरण में राज्य की 152 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें 92 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया। मतगणना आगामी चार मई को होगी।

पांच सितारा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने फरवरी, 2024 की बैठक में होटल को नया प्रस्ताव मानते हुए क्लीयरेंस देने से इनकार कर दिया। इस समिति ने जिस नियम नोटिफिकेशन को लागू करते हुए ताज आमेर होटल को क्लीयरेंस देने से इनकार किया, वह गलत इसलिए हैं, क्योंकि यह नियम-कायदे नए होटलों पर लागू होता है, लेकिन पूर्व में स्थापित उन होटलों पर लागू नहीं होता है, जिनकों पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति दी जा चुकी है।

उधर याचिकाकर्ता की दलीलों का विरोध करते हुए केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया कि याचिका में विशेषज्ञ निकाय की राय को चुनौती दी गई है। ऐसे में अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह होटल नाहरगढ़ सेंचुरी से मात्र 90 मीटर की दूरी पर स्थित है। उन्होंने नियम का उल्लंघन करते हुए कहा कि, नाहरगढ़ सेंचुरी के 1 किलोमीटर के दायरे को ईको सेंसिटिव ज़ोन माना गया है, जहां पर होटल्स का संचालन नहीं किया जा सकता। इस पर अदालत ने मामले को सुनने के बाद कहा कि, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने तर्कहीन फैसला दिया है, क्योंकि जिस नोटिफिकेशन को देखते हुए वन्यजीव क्लीयरेंस रद्द किया गया है, उसमें साफ लिखा है कि यह केवल नए होटलों पर लागू हो सकता है, स्थापित होटलों पर नहीं। इस समिति ने होटल के पक्ष को सही तरह से सुना तक नहीं है। ऐसे में इस आदेश को निरस्त किया जाता है।

ट्रंप पर ईरान वॉर खत्म करने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उनके पास विकल्प हैं, जैसे कि 30 दिन की बढ़ोतरी का अनुरोध करना या अथॉराइजेशन फॉर यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्सेज़ (एयूएमएफ) लेना, लेकिन डेमोक्रेटिक विरोध इसकी प्रक्रिया को जटिल बनाता है।

यदि कानून लागू होता है, तो इसका मतलब है कि ट्रम्प स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकेबंदी कायम नहीं रख सकते।

होर्मुज़ एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जो दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत तेल और गैस की आपूर्ति हैंडल करता है और कुछ रिपोर्टों के अनुसार, यह अमेरिकी रणनीति का केन्द्र है, जिससे चीन को ईंधन रोकने और अमेरिका को महत्वपूर्ण समुद्री स्थानों पर प्रमुख स्थिति में लाने की कोशिश की जा रही है। एक्सियॉन के अनुसार, इसका मतलब यह भी है कि तीन से पांच दिन की वर्तमान युद्धविराम अवधि, जो ट्रम्प ने ईरान को दी थी, शायद ईरान के लिए जीत बन जाएगी।

इसलिए ट्रम्प समय सीमा और कठिन स्थिति के बीच फंस गए हैं; राष्ट्रपति ईरान से ऐसे ही बाहर नहीं आना चाहते, वे कुछ ऐसा हासिल करना चाहते हैं, जिसे अमेरिका की जीत के रूप में बता सकें और नवंबर के मध्यावधि चुनावों के लिए चुनावी लाभ प्राप्त कर सकें।

यदि अमेरिका और ईरान लंबी अवधि का शांति समझौता कर लेते हैं, तो इसे दोनों पक्षों की "जीत" के रूप में दिखाने वाले पर्याप्त प्रावधानों के साथ होना चाहिए।

इससे ट्रम्प वॉर पावर एक्ट के दबाव से बच सकते हैं, सैनिकों को घर बुला सकते हैं और यह दावा कर सकते हैं कि उन्होंने अमेरिका को "अनंत युद्ध" में नहीं घसीटा। यह सैनिकों की स्थिति सुधारने और मिसाइल स्टॉक्स (विशेष रूप से पैट्रियट इंटरसेप्टर और टॉमहॉक) को फिर से भरने का अवसर भी देता है।

संभावना कम है, लेकिन असंभव नहीं। तेहरान ने युद्ध समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है, बशर्ते अमेरिका हवाई हमले बंद करे और नाकेबंदी हटा दे। इसके बदले में, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ फिर से खुल जाएगा।

संपूर्ण रूप से खुले होर्मुज़ से दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति सामान्य होगी, जिसमें भारत भी शामिल है, जो अपनी कच्ची तेल जरूरतों का लगभग 40 प्रतिशत पश्चिम एशियाई रिफाइनरियों से खरीदता है।

चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम को जमानत मिली

शिलांग, 28 अप्रैल। मेघालय की राजधानी शिलांग की एक अदालत ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में अहम फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी है। वह अपने पति की हत्या के आरोप में पिछले कई महीनों से शिलांग जेल में थी। सोनम को चौथी जमानत याचिका पर यह राहत मिली। इससे पहले उसकी तीन याचिकाएं अदालत की ओर से खारिज कर दी गई थीं। पीड़ित के भाई विपिन रघुवंशी ने इस निर्णय की पुष्टि की है। शिलांग सेशन कोर्ट ने बीते सप्ताह सोनम की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद सोमवार को जमानत का आदेश दिया।

'अत्याधुनिक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें शामिल हैं" विकसित की हैं, जो "हमारे घरेलू क्षेत्र को खतरे में डालने" के लिए डिज़ाइन की गई हैं। वे अमेरिका में विकसित हो रही अगली पीढ़ी की 'गोल्डन डोम' मिसाइल रक्षा प्रणाली पर सुनवाई के दौरान, अमेरिकी सीनेट कमेटी ऑन आर्म्ड सर्विसेज के सामने बोल रहे थे। देश की वर्तमान मिसाइल रक्षा क्षमताओं का वर्णन करने के लिए पूछे जाने पर, उन्होंने कहा, "आज हमारे पास एक बहुत सीमित ग्राउंड-आधारित सिंगल-लेयर होमलैंड डिफेंस सिस्टम है, जिसे विशेष रूप से उत्तर कोरिया से छोटे पैमाने के दुर्भावनापूर्ण हमले के खिलाफ डिज़ाइन किया गया था।" यह स्पष्ट और गंभीर आकलन उन चिंताओं के बीच आया है जो चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया जैसी राष्ट्रों की विकसित होती सैन्य क्षमताओं को लेकर हैं, जिससे वॉशिंगटन को अपनी घरेलू मिसाइल रक्षा में प्रमुख खामियों को स्वीकार करना पड़ा।

राजीव गांधी की हत्या का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में दोषी ठहराए गए एजी पेरारिवलन, जिन्हें 31 साल की जेल की सजा के बाद 2022 में रिहा किया गया था, अब चेन्नई के मद्रास हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील के रूप में अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू कर चुके हैं।

वही कानूनी व्यवस्था, जिसमें पेरारिवलन ने 31 साल बिताए, अब उन्हें मद्रास हाई कोर्ट में वकील के रूप में अभ्यास करने का अवसर दे रही है। वे अब 54 वर्ष के हैं।

सोमवार को वकील के गाउन में उन्होंने तमिलनाडु और पुडुचेरी बार एसोसिएशन में वकील के रूप में नामांकन कराया।

1991 से जेल में बिताए अपने वर्षों को अनुभव का स्रोत बताते हुए, पेरारिवलन ने कहा कि उनका उद्देश्य गलत गिरफ्तारी, न्याय में देरी, और अंडरट्रायल के अधिकारों से संबंधित मामलों पर काम करना है, ताकि व्यक्तिगत अनुभव को कानूनी वकालत में बदला जा सके।

उन्होंने कहा, "मैं उन कैदियों को कानूनी सहायता देने पर ध्यान केन्द्रित करूंगा, जिनकी अक्सर प्रभावी प्रतिनिधित्व तक पहुँच नहीं होती।"

मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी ने पेरारिवलन के नामांकन समारोह में भाग लिया।

तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल के अध्यक्ष पी एस अमलराज और उपाध्यक्ष एस प्रभाकरण भी उपस्थित थे।

वकील सी के चंद्रशेखर ने नामांकन प्रस्ताव पेश किया, जबकि नामांकन समिति के अध्यक्ष के बालू ने उन्हें शपथ दिलाई।

पेरारिवलन केवल 19 वर्ष के थे, जब उन्हें 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया, यह हत्या लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (लिट्टे) ने की थी।

बंगाल के चुनाव, एक ही हीरो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से अभिषेक बनर्जी के अलावा किसी भी अन्य प्रत्याशी को मतदाताओं से कोई वोट नहीं मिल पाता था। पिछले लोकसभा चुनाव में, अभिषेक बनर्जी ने सबसे अधिक मतों से जीतने का विवादित रिकॉर्ड बनाया। उन्हें सात लाख वोट मिले, जो लगभग 90 प्रतिशत के करीब थे।

इस बार भी, तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त थी कि उनका अधीनस्थ जहांगीर उनके पक्ष में सभी वोट दिलायेगा, अन्य किसी को भी वोट नहीं मिलने चाहिए। तरीका यह था कि मतदाताओं के पहचान पत्र इकट्ठे किए जाएं और फिर इनका उपयोग पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट डालने में किया जाए। इसका परिणाम यह होना था कि कोई भी मतदाता अपनी मर्जी से वोट नहीं डाल सकता था। निर्वाचन क्षेत्र मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल है और इन्हें पार्टी द्वारा फर्जी मतदान के लिए कब्ज़ा लिया जाये। केन्द्रीय बल विशेष रूप से डायमंड हार्बर निर्वाचन क्षेत्र में यह ठान चुका था कि यह स्पष्ट कर दिया जाए कि अब गुंडों का राज नहीं चलेगा।

दरअसल, यह दृश्य ही आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। केन्द्रीय बल स्वयं तृणमूल कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं, जो क्षेत्र के लोगों को आतंकित करते थे। लोग उन्हें सर्वेसर्वा मानते थे। अब जब उन्हें खुलेआम पकड़ा और घसीटा जा रहा है या वे पकड़े जाने के डर से अपने अड्डों से भाग रहे हैं, यह दृश्य पूरे बंगाल के लिए एक नया भरोसा दिलाने वाला है।

सत्ताधारी पार्टी द्वारा खेले जा रहे काले खेल के चलते, इस समय वामपंथी पार्टियों की भूमिका इस प्रक्रिया में गुप्त जानकारियाँ उपलब्ध कराने की है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने वामपंथियों के खिलाफ अपनी आक्रामकता बढ़ाई थी और इसकी सुप्रीमो ममता बनर्जी अक्सर वामपंथियों से कठोर लड़ाई लड़ती थीं।

हालाँकि, वामपंथी गुस्से और निराशा में हैं कि देश की कानून-व्यवस्था मशीनरी स्थानीय गुंडों को इतने प्रभावी ढंग से समाप्त कर सकती है, जैसे वे पारंपरिक बाउलिंग खेल के मात्र नौ पिन हों। वे पुलिस व्यवस्था और केन्द्रीय बलों की आलोचना कर रहे हैं, शायद, चुनावी प्रक्रिया को साफ-सुथरा करने की खातिर। पुलिस, मुख्य रूप से केन्द्रीय बलों द्वारा क्षेत्र पर नियंत्रण, बंगाल सरकार पुलिस बल को बाहर रखकर, पहले चरण के जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में जबरदस्त सहयोग दे रहा है। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद, तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी अब तक कोई भी असामान्य कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं खड़ी कर सके हैं। बंगाल दूसरे चरण के निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव के लिए उम्मीद लगाए हुए है।

दिल्ली -पटियाला रेलवे ट्रैक पर बम विस्फोट

अनिल अंबानी ग्रुप की तीन हजार करोड़ की संपत्ति कुर्क

गुजरात की सभी 15 महानगर पालिकाओं में भाजपा की जीत

ईरान परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन का उपाध्यक्ष बना

प्र.मंत्री ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सिक्किम पहुंचने के एक दिन बाद, प्रधानमंत्री मोदी को एक अलग रूप में देखा गया, अपनी सामान्य कुर्ता को पीछे छोड़कर ट्रैक पैंट और फुटबॉल स्पाइक पहनकर फुटबाल खेलते दिखे।

इस राजनीतिक चाल की टाइमिंग को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। सिक्किम के पड़ोसी राज्य बंगाल में फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं है, बल्कि यह राज्य की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। प्रधानमंत्री की यह पहल बंगाल चुनाव से पहले कुछ लाभ हासिल करने और राज्य में गहरे खेल प्रेम के बीच एक सूक्ष्म संदेश देने की कोशिश लग रही है।

याद करें, 2021 विधानसभा चुनावों के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की वह तस्वीर जब वे व्हीलचेयर में बैठकर रैली में फुटबॉल फेंक रही थीं और "खेला होगा" के नारे लग रहे थे। यह नारा विभिन्न वर्गों में गूंजा और टीएमसी के लिए एक जोरदार मुद्दा बन गया, जिससे पार्टी ने निर्णायक दो-तिहाई बहुमत हासिल किया।

चंडीगढ़ , 28 अप्रैल। पंजाब-हरियाणा बार्डर पर शंभू की सीमा में बीती रात दिल्ली-पटियाला रेलवे ट्रैक पर बम धमाका हुआ है। कहा जा रहा है कि जिस संदिग्ध ने विस्फोटक लगाया,

- **विस्फोट लगाने वाले संदिग्ध की हादसे में मौत हो गई।**

उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव के टुकड़े आज सुबह बरामद किए हैं। धमाके के कारण कई घंटे तक रेलवे ट्रैक बाधित रहा। यह धमाका पटियाला जिला के गांव बठोनियां के निकट जंगल में हुआ है। यहां रेलवे ट्रैक का कुछ हिस्सा घने जंगल में है। आतंकवाद के दौर में भी इस क्षेत्र में अकसर घटनाएं होती रही हैं।

पटियाला के एसएसपी वरूण शर्मा ने बताया कि बीती रात शंभू के निकट रेलवे ट्रैक पर धमाके की सूचना मिली। जिसके बाद वे स्वयं, डीआईजी पटियाला रेंज, जीआरपी तथा आरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जहां धमाका हुआ, वहां गहरा गड्ढा बन गया।

ईडी ने मनी लॉडरिंग एक्ट के तहत ये संपत्तियां जब्त की थीं

नई दिल्ली, 28 अप्रैल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह (आरएएजी) की कंपनियों के खिलाफ जारी धनशोधन जांच के अंतर्गत 3,034.90 करोड़ रुपये की नई संपत्तियां जब्त की हैं।

केन्द्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को जारी बयान में बताया कि ईडी ने मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 3,034.90 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। एजेंसी के मुताबिक, कुर्क की गई संपत्तियों में मुंबई का एक फ्लैट, खंडाला का फार्महाउस, सानंद की जमीन तथा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के 7.71 करोड़ शेयर शामिल हैं। इस तरह रिलायंस अनिल अंबानी समूह से जुड़े मामलों में अब तक 19,344 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।

ईडी ने कहा कि कुर्क की गई

- **ईडी ने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों की अब तक की कुल राशि 19,344 करोड़ रु. हो गई है।**

संपत्तियां रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर-इंफ्रा) की हैं। इनमें मुंबई में एक फ्लैट, खंडाला (महाराष्ट्र का एक हिल स्टेशन) में एक फार्महाउस, साणंद (अहमदाबाद) में कुछ भूखंड और आर-इंफ्रा के 7.71 करोड़ शेयर शामिल हैं।

केन्द्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया है।

अहमदाबाद, 28 अप्रैल। गुजरात की सभी 15 महानगरपालिकाओं के चुनाव में इस बार भी भाजपा का दबदबा कायम रहा। सूरत महानगरपालिका में भाजपा ने एक बार फिर प्रचंड जीत दर्ज

- **सबसे शानदार जीत सूरत में मिली जहां पार्टी ने 120 में से 112 सीटें जीती**

करते हुए 120 में से 115 सीटों पर कब्जा कर लिया है। पिछले 30 वर्षों से जारी भाजपा का एकछत्र शासन अगले पांच वर्षों तक भी बरकरार रहेगा।

वर्ष 2021 में 27 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी इस बार मात्र 4 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस, जो पिछली बार खाता भी नहीं खोल सकी थी, इस बार केवल 01 सीट जीतने में सफल रही है। इन चुनावों का आयोजन एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) प्रक्रिया और 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद हुआ।

अमेरिका ने इस पर सख्त नाराजगी जाहिर की और इसे शर्मनाक बताया

न्यूयॉर्क, 28 अप्रैल। अमेरिका ने ईरान को संयुक्त राष्ट्र चार्टर विशेष समिति और परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन का उपाध्यक्ष चुने जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले ईरान को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का भी उपाध्यक्ष चुना जा चुका है। अमेरिका के तेवर संयुक्त राष्ट्र में सोमवार को परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बनी संधि की समीक्षा शुरू होने पर दिखे। बैठक में अमेरिका और ईरान के बीच तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तीखी बहस हुई।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सम्मलेन के उद्घाटन सत्र में हथियार नियंत्रण और अप्रसार मामलों के लिए अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने कहा कि भले ही ईरान के इरादों और उसके परमाणु कार्यक्रम से निपटने के तरीकों को लेकर

- **अमेरिका ने कहा ईरान का परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन का उपाध्यक्ष बनना इस सम्मेलन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है।**

अलग-अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन ईरान ने संधि की अवमानना की है। येव ने कहा, "इस समीक्षा सम्मेलन का इस्तेमाल परमाणु अप्रसार संधि की अखंडता की रक्षा करना है। सम्मेलन में ईरान को जवाबदेह भी ठहराया जाना चाहिए। येव ने कहा कि हमने ईरान को ही उपाध्यक्ष चुन लिया है। अमेरिकी नेता ने कहा, "यह बेहद शर्मनाक है और इस सम्मेलन की विश्वसनीयता पर एक धब्बा है।"

वियना स्थित संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत रजा नजाफी ने अमेरिका के आरोपों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया है।

इस सम्मेलन में कुल 34 उपाध्यक्ष होते हैं। परमाणु अप्रसार संधि में शामिल 191 सदस्य देश इसकी हर पांच साल में समीक्षा करते हैं। यह संधि 1970 में लागू हुई थी। उपाध्यक्ष के तौर पर ईरान की दावेदारी का गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने समर्थन किया। इसमें 121 विकासशील देश शामिल हैं। उपाध्यक्ष पद पर अमेरिका की दावेदारी का ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात ने समर्थन किया है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की। रूस ने ईरान को निशाना बनाए जाने पर आपत्ति जताई है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908